के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या संचार मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों के 31 पद खाली हैं और क्या इन पदों पर तदर्थ नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र अन्य मंत्रालयों से और संघ लोक सेवा आयोग से नहीं मंगवाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और विशेष रूप से मंत्रालयों में भविष्य में वरिष्ठ अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों में की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : (क) तदर्थ नियुक्तियां केवल तभी की जाती हैं जब पदों पर भर्ती के लिए कोई नियम/विनियम नहीं बनाए गए हैं अथवा सेवा की आवश्यकताओं के कारण ऐसी नियुक्तियां किया जाना आवश्यक हो क्योंकि भर्ती नियमों में निर्धारित क्रियाविधि का तुरन्त पालन नहीं किया जा सकता । तदर्थ नियुक्तियां, यथासम्भव, सम्बन्धित भर्ती नियमों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार ही करनी होती हैं । अत: यह पदों के भरे जाने के लिए निर्धारित भर्ती पद्धति पर निर्भर करता है कि अन्य मंत्रालयों से भी आवेदन पत्र मांगे जाने हैं अथवा नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Legislation for Farm Workers

3937. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Government differ sharply on the question of Central legislation for farm workers;

(b) if so, whether the question of enacting the Central law has been under the study for a long time now with the Union Government;

(c) if so, whether the response received from the State Government show that not all of them are agreed on the advisability on Central legislation;

(d) if so, what are the main reasons for their rejection and whether Government has decided to appoint a working group to go into the whole matter before any Central legislation is taken; and

(e) if so, by what time this group is likely to submit its recommendations to the Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, since July 1980, when the proposal was approved by the Central Standing Committee on Rural Unorganised Labour.

(c) Yes, Sir.

(d) Difficulties in the implementation of a uniform legislation have been expressed because diverity of conditions from State to State and even within the State. The Labour Minister's Conference recommended in depth study by a working Group.

(e) The Working Group has already considered the matter and a final view has yet to be taken by Government.